www.railsamacharbureau.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"भारतीय रेल की असली ताकत उसके इंजन में नहीं, करोड़ों यात्रियों के भरोसे में है।"

"भारतीय रेल सिर्फ यात्रियों को नहीं, पूरे देश के सपनों को मंजिल तक पहुँचाती है।"

वर्ष-36 अंकः12-13 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 16 जून - 15 जुलाई 2026 (सयुक्तांक) पृष्ठ 12, मूल्य:20 रु. मात्र. डाक खर्च (रंगीन सहित)

राजस्थान-बिहार रेल संपर्क को नई उड़ान

जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और देश के पहले मेगा कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ

सूत्र - रे.स.ब्यू - केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 21 जून 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस नई रेल सेवा का शुभारंभ किया, जिसका संचालन सप्ताह में छह दिन किया जाएगा। इस अवसर पर खातीपुरा में नवनिर्मित मेगा कोचिंग टर्मिनल तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह रेल सेवा राजस्थान और बिहार के मिथिला क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक संपर्क को मजबूत करेगी तथा प्रवासी बिहारवासियों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुंदरपुरा स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को राजस्थान और बिहार के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे व्यापार, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने नई रेल सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राजस्थान में कार्यरत बिहार के लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी। 205 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल को देश का पहला ऐसा टर्मिनल बताया गया, जहां विभिन्न प्रकार की ट्रेनों का अनुरक्षण एक ही स्थान पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे के 41 छोटे एवं मध्यम स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विकास और उन्नयन कार्यों का भी शुभारंभ किया गया।

मुख्य बिंदुः

- जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, सप्ताह में 6 दिन संचालन।
- राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क, व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
- खातीपुरा में 205 करोड़ रुपये की लागत से देश के पहले मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन।
- मेगा कोचिंग टर्मिनल में वंदे भारत, डेमू, एलएचबी सहित विभिन्न प्रकार की ट्रेनों का अनुरक्षण संभव होगा।
- केंद्रीय रेल मंत्री ने खाटूश्याम जी श्रद्धालुओं के लिए सुंदरपुरा स्टेशन निर्माण की घोषणा की।
- राजस्थान में पहली बार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का रेलवे बजट आवंटन और 76,800 करोड़ रुपये के रेल कार्य प्रगति पर।
- राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण तथा 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन।
- उत्तर पश्चिम रेलवे के 41 छोटे एवं मध्यम स्टेशनों पर नई यात्री सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का विकास।
- 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत।
- नई रेल सेवा से विशेष रूप से प्रवासी बिहारवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

ऐतिहासिक कादियां-ब्यास रेल परियोजना

लगभग 100 वर्षों बाद पुनर्जीवित : श्री रवनीत सिंह बिट्टू

सूत्र - रे.स.ब्यू -रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार ने लंबे समय से लंबित कादियां ब्यास नई रेल लाइन परियोजना को पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे अवसंरचना को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 39.68 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित ब्रॉडगेज रेल लाइन गुरदासपुर जिले के कादियां को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,400 करोड़ है और इसका क्रियान्वयन उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाएगा। रेल मार्ग कादियां, धपाई, घुमान, बुटाला, सठियाला और ब्यास सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। परियोजना के अंतर्गत घुमान और बुटाला में दो क्रॉसिंग स्टेशन, 11 प्रमुख पुल, 121 लघु पुल, 54 रोड अंडर ब्रिज, आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार प्रणाली तथा 'कवच' प्रणाली का प्रावधान

"39.68 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर लगभग ₹1,400 करोड़ की लागत आएगी पंजाब में संपर्क, पर्यटन एवं विकास को मिलेगा बड़ा बढ़ावा"

किया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि इस रेल लिंक की परिकल्पना ब्रिटिश काल में की गई थी और वर्ष 1928–29 में इसे स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन बाद में परियोजना बंद हो गई। बाद में इसे सामाजिक रूप से वांछनीय रेल संपर्क परियोजना के रूप में पुनर्जीवित किया गया, हालांकि विभिन्न कारणों से कार्य आगे नहीं बढ़ सका। अब परियोजना को फिर से गति दी गई है और संशोधित विस्तृत अनुमान रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों में अमृतसर पठानकोट रेलखंड के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम करेगी। परियोजना से किसानों, व्यापार, परिवहन, लघु उद्योगों और रोजगार सृजन को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही कादियां, ब्यास, डेरा बाबा नानक, घुमान और अन्य प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में उन्होंने माझा क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

Scanned with OKEN Scanner

बेंगलुरु-तुमकूर रेल सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होगा और मजबूत

सूत्र-रे.स.ब्यू.- कर्नाटक के सबसे व्यस्त रेल रूट्स में से एक बेंगलुरु तुमकूर सेक्शन पर रेल संचालन को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत दक्षिण पश्चिम रेलवे के इस सेक्शन पर मौजूदा 1X25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को आधुनिक 2X25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा।

यह परियोजना 120 ट्रैक किलोमीटर (TKM) क्षेत्र में लागू की जाएगी और इसकी स्वीकृत लागत 162.57 करोड़ है। बेंगलुरु तुमकूर सेक्शन महत्वपूर्ण हाइली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (HUN) रूट-10 का हिस्सा है, जो पुणे, हुब्बल्ली, चिक्कजाजुरु, बीरूर, तुमकूर, बेंगलुरु, सेलम और कन्याकुमारी जैसे प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है।

2X25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम लागू होने से ट्रेनों के लिए पावर सप्लाई व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे इस सेक्शन पर बढ़ते रेल ट्रैफिक को अधिक दक्षता के साथ संभाला जा सकेगा। साथ ही, भारी मालगाड़ियों और लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के संचालन में भी मदद मिलेगी तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

यह परियोजना बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों को सेवा देने वाले इस महत्वपूर्ण रेल रूट पर क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही, कर्नाटक और दक्षिण भारत में यात्री एवं माल परिवहन को और अधिक सुगम बनाएगी।

यह परियोजना भारतीय रेल के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और व्यस्त रेल कॉरिडोरों पर बेहतर परिचालन सुनिश्चित करने के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी।

उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी ने रेलवे बोर्ड के साथ की अहम बैठक

सूत्र-रे.स.ब्यू.- उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने और नई रेल परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं, नई प्रस्तावित रेल लाइनों तथा रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल संपर्क उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थाटन, निवेश और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल बताते हुए इसके कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि परियोजना के पूरा होने से चारधाम यात्रा विशेषकर बदरीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बनेगी।

बैठक के दौरान टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि परियोजना का सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना पर शीघ्र प्रगति की अपेक्षा जताते हुए कर्णप्रयाग बागेश्वर तथा किच्छा खटीमा रेल लाइन परियोजनाओं को भी क्षेत्रीय संतुलित विकास और भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर और टनकपुर स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे के उन्नयन का सुझाव दिया। साथ ही आगामी कुंभ और कांवड़ मेले के मद्देनजर हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता भी बताई, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।

बैठक में हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण से राज्य में निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। बैठक के अंत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि चर्चा में उठाए गए सभी विषयों पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा।

दिसंबर 2028 तक पूरी हो जाएगी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित राज्य की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित राज्य की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति देने तथा इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल कर इसकी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन परियोजना की डीपीआर को भी शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया गया।

बैठक में हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना पर भी चर्चा हुई। रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि हरिद्वार-मोतीचूर रेल लाइन दोहरीकरण को स्वीकृति मिल चुकी है और यह कार्य दो चरणों में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अतिक्रमण हटाने में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मेरठ-ऋषिकेश आर.आर.टी.एस कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा हुई। ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक प्रस्तावित 78 किलोमीटर लंबे संरेखण की डीपीआर तैयार किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

27 जून से नियमित रूप से चलेगी पुणे-दानापुर अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल मंडल को मिलेगा बेहतर रेल संपर्क

सूत्र - रे.स.ब्यू.- यात्रियों को बेहतर, किफायती और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन 27 जून से पुणे दानापुर पुणे अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू करने जा रहा है। नई सेवा पुणे एवं दानापुर के बीच मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ते हुए बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगी। यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर भी ठहरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक नया विकल्प मिलेगा।

ट्रेन संख्या 11431 पुणे दानापुर अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को पुणे से रवाना होकर निर्धारित समय पर इटारसी और नरसिंहपुर होते हुए दानापुर पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 11432 दानापुर पुणे अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को दानापुर से प्रस्थान कर इटारसी सहित विभिन्न स्टेशनों से होते हुए पुणे पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार, यह नई सेवा 27 जून 2026 से पुणे और 29 जून 2026 से दानापुर से नियमित रूप से संचालित होगी।

इस ट्रेन के संचालन से भोपाल मंडल के इटारसी क्षेत्र के यात्रियों को पुणे, भुसावल, जबलपुर, कटनी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा। साथ ही यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और लंबी दूरी के सफर में समय की बचत का लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा एवं आरक्षण संबंधी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलमदद ऐप या निकटतम रेलवे स्टेशन से प्राप्त करने की अपील की है।

दानापुर मंडल संसदीय समिति की बैठक में रेल विकास और यात्री सुविधाओं पर हुई व्यापक चर्चा

सूत्र - रे.स.ब्यू.- दानापुर मंडल की 'मंडल संसदीय समिति' की बैठक 23 जून 2026 को महेंद्रू घाट, पटना में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने की, जिसमें दानापुर मंडल क्षेत्र के सांसदों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा रेलवे के समग्र विकास को लेकर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए।

बैठक में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार सहित मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सांसदों ने रेल अवसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने तथा भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया।

बैठक के प्रारंभ में महाप्रबंधक ने सांसदों एवं उनके प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए दानापुर मंडल में यात्री सुविधाओं, आधारभूत संरचना विकास और नई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दानापुर मंडल ने वर्ष 2025 में अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाई और निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के समयबद्ध संचालन में सुधार, त्योहारों एवं व्यस्त सीजन में विशेष ट्रेनों के संचालन तथा यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं।

महाप्रबंधक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 518 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया तथा विभिन्न ट्रेनों में 2,262 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। वहीं, 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकरण जारी है। पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनसेट अनुरक्षण डिपो और हार्डिंग पार्क में पांच नए प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जबकि राजगीर कोचिंग कॉम्प्लेक्स और फतुहा मेगा कोचिंग टर्मिनल परियोजनाओं पर भी चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है।

बैठक के अंत में महाप्रबंधक ने सांसदों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सुझाव भविष्य की रेल विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अब डीआरएम से सीधे कहें अपनी बात, कोटा मंडल ने शुरू की नई जनसुनवाई पहल

सूत्र-रे.स.ब्यू.- पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए नई जनसुनवाई व्यवस्था शुरू की है। इस पहल के तहत रेल कर्मचारी और आम नागरिक अब प्रत्येक गुरुवार सायं 5 बजे से 6 बजे तक पूर्व पंजीकरण के आधार पर सीधे मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) से मिलकर अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के निर्देशन में शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को मंडल के सर्वोच्च अधिकारी तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराना और लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सुनवाई के लिए इच्छुक कर्मचारियों और नागरिकों को पहले अपनी समस्या संबंधित शाखा अधिकारी अथवा अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीआरएम कार्यालय में समय दिया जाएगा।

रेल प्रशासन के अनुसार प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। यदि किसी सप्ताह गुरुवार को बैठक आयोजित नहीं हो पाती है, तो उसी सप्ताह शुक्रवार को शिकायतकर्ताओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, मंडल रेल प्रबंधक प्रत्येक गुरुवार सायं 4 बजे से 5 बजे तक कोटा मंडल के ठेकेदारों की शिकायतों और समस्याओं की भी सुनवाई करेंगे। ठेकेदारों को इसके लिए प्रत्येक मंगलवार सायं 4 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकरण कराना होगा। रेल प्रशासन का मानना है कि यह पहल कर्मचारियों, यात्रियों और आमजन की समस्याओं के समाधान को अधिक सुगम बनाएगी तथा प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद एवं विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी जानकारी कोटा मंडल के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से दी गई।

छपरा-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ, बिहार में बुलेट ट्रेन लाने की घोषणा

सूत्र-रे.स.ब्यू.- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छपरा जंक्शन से छपरा आनंद विहार टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12527/12528) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने बिहार में भविष्य में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य जारी है और राज्य का शत-प्रतिशत रेल विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। रेल मंत्री ने कहा कि नई सुपरफास्ट सेवा छपरा और दिल्ली के बीच संपर्क को मजबूत करेगी तथा यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार रेलवे और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। नई ट्रेन के शुभारंभ को लेकर छपरा जंक्शन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और यात्रियों ने इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा बताया।

रेल संपर्क को मिलेगी नई मजबूती, कासगंज-लखनऊ एक्सप्रेस को मंजूरी

सूत्र-रे.स.ब्यू.- पीलीभीत के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस नई रेल सेवा से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर समेत पूरे तराई क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। प्रस्तावित ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहिबुल्लापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर लखनऊ तक पहुंचेगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को राजधानी से सीधा और सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध होगा।

नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से दैनिक यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को यात्रा के बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ ही क्षेत्र में आवागमन सुगम होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बेहतर रेल संपर्क से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच सकता है तथा विभिन्न जिलों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जितिन प्रसाद ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के स्टेशनों पर चार ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव की मंजूरी दी

दिल्ली-सत्रेद पैसेंजर, अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस, बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस और जयपुर-आसरवा एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नए ठहराव से हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख स्टेशनों पर चार ट्रेनों के लिए अतिरिक्त ठहराव को मंजूरी दी है। इस पहल से स्थानीय यात्रियों, छात्रों, किसानों, व्यापारियों तथा अन्य रेल उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वीकृत ठहराव के तहत 54085/54086 दिल्ली सत्रोद पैसेंजर ट्रेन को हरियाणा के पटुवास मेहराना स्टेशन पर, 14619/14620 अगरतला फिरोजपुर एक्सप्रेस और 14717/14718 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस को हरियाणा के हांसी स्टेशन पर तथा 12981/12982 जयपुर आसर्व एक्सप्रेस को राजस्थान के बिजैनगर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया गया है। रेलवे के अनुसार यह निर्णय विस्तृत परिचालन मूल्यांकन और यात्री मांग की समीक्षा के बाद लिया गया है तथा प्रस्तावित ठहराव परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक पाए गए हैं।

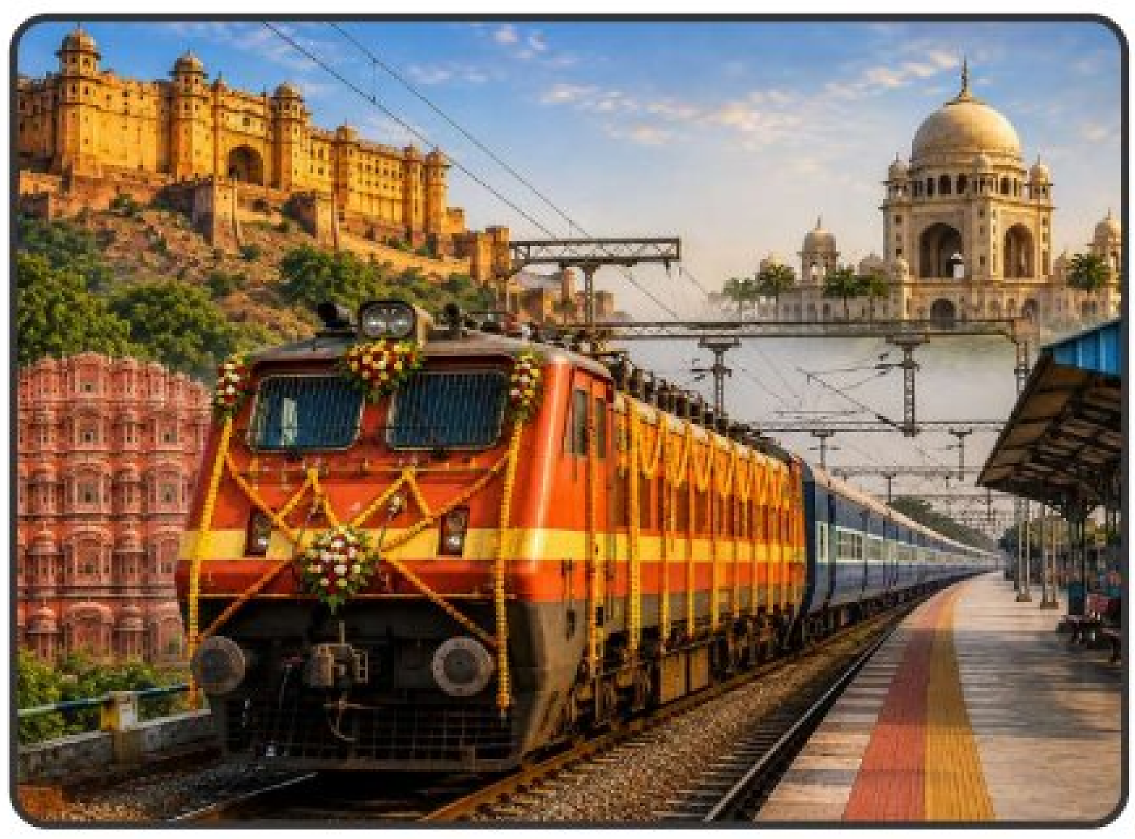

पटुवास मेहराना के लिए रेल सपंर्क सुविधा में सुधार किया गया है।

रेवाड़ी-भिवानी खंड पर स्थित पटुवास मेहराना स्टेशन पर वर्तमान में 3 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें और 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली-सत्रोद पैसेंजर ट्रेन संख्या 54085/54086 के लिए ठहराव की मंजूरी से आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए रेल संपर्क और मजबूत होगा और उन्हें दैनिक रेल परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। इस ट्रेन के लिए पहले सबसे नजदीकी स्टेशन झारिली और चरखी दादरी थे, जो क्रमशः लगभग 6 किमी और 7 किमी दूर स्थित थे। नया स्टेशन बनने से नजदीकी स्टेशनों पर निर्भरता कम होगी, शुरुआती एवं अंतिम सपंर्क सुविधा में सुधार होगा और स्थानीय यात्रियों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी।

हांसी के लिए उन्नत संपर्क सुविधा

भिवानी-हिसार खंड पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन हांसी में पहले से ही 8 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें, 7 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें और 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जिससे यह क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण यात्री केंद्र बन गया है। 14619/14620 अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और 14717/14718 बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस के लिए नए ठहराव की मंजूरी मिलने से हांसी और आसपास के इलाकों के यात्रियों को अतिरिक्त लंबी दूरी की रेल सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा। पहले ये ट्रेनें भिवानी सिटी और हिसार में रुकती थीं, जो क्रमशः लगभग 37 किमी और 25 किमी दूर स्थित हैं। नए ठहराव से यात्रा में सुविधा बढ़ेगी, देश के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों से सपंर्क सुविधा बेहतर होगी और यात्रियों को अपने निकटतम स्टेशन से यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे।

बिजाईनगर के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा

राजस्थान के बिजाईनगर स्टेशन पर वर्तमान में 19 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें और 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जो अजमेर-चंदेरिया खंड पर इसके महत्व को दर्शाती हैं। बिजाईनगर आने-जाने वाले यात्रियों को अब 12981/12982 जयपुर-आसरवा एक्सप्रेस के स्वीकृत ठहराव का लाभ मिलेगा। पहले यह ट्रेन नासिराबाद और भीलवाड़ा में रुकती थी, जो क्रमशः लगभग 42 किमी और 67 किमी दूर स्थित हैं। इस नए ठहराव से इस महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय सेवा तक सीधी पहुँच मिलेगी, राजस्थान और गुजरात के बीच संपर्क बेहतर होगा और इस क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों, छात्रों और व्यावसायिक यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

यात्री–कैंद्रित निर्णय

यह मंजूरी भारतीय रेलवे द्वारा बेहतर रेल संपर्क सुविधा और त्वरित सेवा योजना के माध्यम से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। जिन स्टेशनों पर यात्रियों की मांग है और परिचालन व्यवहार्यता स्थापित हो चुकी है वहां ठहराव शुरू करके भारतीय रेलवे देश भर के लोगों के लिए रेल यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

नन्हे यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, कोटा मंडल के 17 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे आधुनिक बेबी केयर सेंटर

सूत्र-रे.स.ब्यू - कोटा रेल मंडल में 'प्रोजेक्ट आयुष्मान' और 'मदर्स कॉर्नर' योजना के अंतर्गत मंडल के 17 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक 'बेबी केयर सेंटर' यानी फीडिंग एवं केयर रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़भाड़ के बीच महिला यात्रियों और उनके मासूम शिशुओं को एक सुरक्षित, स्वच्छ और पूरी तरह से निजी वातावरण मिल सकेगा ताकि माताएं बिना किसी संकोच के अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें और उनकी उचित देखरेख कर सकें।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जनसंपर्क अधिकारी सौरभ जैन के अनुसार, इन विशेष केंद्रों को तैयार करने के लिए स्टेशनों पर जगह को चिन्हित करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। यह सुविधा कोटा रेल मंडल के 17 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। जिनमें कोटा, भरतपुर, बयाना, हिंडौन, श्रीमहावीरजी, गंगापुर सिटी, बूंदी, विक्रमगढ़ आलोट, छबड़ा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ सिटी, लाखेरी, इंद्रगढ़, रामगंजमंडी और सुवासरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। इन नवनिर्मित बेबी केयर सेंटर्स में महिला यात्रियों के बैठने, एसी तथा टेबल और डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रेलवे की इस अनूठी पहल से नवजात बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को सफर के दौरान एक नई राहत और मानसिक सुकून मिलेगा।

लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर विकास कार्यों का जायजा, महाप्रबंधक ने दिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश

सूत्र - रे.स.ब्यू - उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने 22 जून 2026 को लखनऊ पहुंचकर स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

अपने दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने लखनऊ बाराबंकी रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया, जिसमें रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का आकलन किया गया। इसके बाद उन्होंने मल्हौर स्टेशन का दौरा कर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत संचालित विकास परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया।

निरीक्षण कार्यक्रम के अगले चरण में महाप्रबंधक बाराबंकी स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों, स्टेशन अवसंरचना और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया तथा सभी परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

दौरे के समापन पर महाप्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास परियोजनाओं और यात्री सुविधा संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

स्टेशन मास्टरों को मिलेंगे अधिक अधिकार, रेलवे ने शुरू की सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण की पहल

सूत्र-रे.स.ब्यू - केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक में स्टेशन मास्टरों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के समक्ष आने वाली प्रचालनगत और प्रशासनिक चुनौतियों की समीक्षा की गई तथा उन्हें अधिक अधिकार, बेहतर संसाधन और आधुनिक तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया।

रेलवे ने स्टेशन मास्टरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक एवं प्रचालनगत शक्तियों में वृद्धि, वित्तीय अधिकारों के विस्तार, करियर उन्नति के बेहतर अवसर और उच्च प्रबंधन स्तरों तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसे उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही मल्टी-ट्रैक और उच्च यातायात वाले रेलखंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति तथा रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मोबाइल ऐप आधारित पेपरलेस कार्य प्रणाली और एकीकृत स्टेशन प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और यात्रियों की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेटर और अन्य उन्नत तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा हुई, ताकि स्टेशन मास्टर जटिल परिचालन स्थितियों और आपात परिस्थितियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

रेल मंत्री ने स्टेशन स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने, बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में महिला स्टेशन मास्टरों और महिला पॉइंट्समैनों की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपकरणों और कार्यस्थल सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विचार किया गया। रेलवे का मानना है कि इन पहलों से स्टेशन प्रबंधन अधिक उत्तरदायी, कुशल और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकेगा, जिससे देशभर के लाखों यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

डॉयूमेंट्री से विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे की विरासत को मिला नया मंच सोलन में 'विरासत के मुसाफिर' का विशेष प्रदर्शन, युवा पीढ़ी तक इतिहास पहुंचाने की अनूठी पहल

सूत्र-रे.स.ब्यू- हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर और यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे के गौरवशाली इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'विरासत के मुसाफिर' का विशेष प्रदर्शन सोलन स्थित होटल पैरागॉन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम सोलन डॉ. पूनम बंसल ने किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन करते हुए इसे प्रदेश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। कार्यक्रम के दौरान कालका-शिमला रेलवे के निर्माण, इसके ऐतिहासिक महत्व और हिमाचल के विकास में इसकी भूमिका को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शकों को इस विश्व धरोहर के गौरवशाली अतीत और उससे जुड़े अनेक रोचक तथ्यों से अवगत कराया गया। सोलन होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने होटल पैरागॉन में हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों और कालका-शिमला रेलवे से जुड़ी विरासत को संजोकर रखा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक प्रदेश के समृद्ध इतिहास को नजदीक से जान सकें। उन्होंने कहा कि यह पहल उन लोगों के योगदान और बलिदान को सम्मान देने का प्रयास है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही युवा पीढ़ी को भी अपनी विरासत और इतिहास से जोड़ने का यह एक सार्थक माध्यम है। वर्मा ने बताया कि इस विषय पर एक विशेष वीडियो भी तैयार किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक कालका-शिमला रेलवे के गौरवशाली इतिहास की जानकारी पहुंचाई जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

रेलवे की नई मंजूरी से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सफर होगा सुगम

भारतीय रेल ने सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए पूर्वी तट रेलवे के 631 रूट किलोमीटर पर 270 करोड़ रुपये की लागत से कवच लगाने को मंजूरी दी

सूत्र-रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के जरिए रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 270 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वी तट रेलवे के 631 रूट किलोमीटर (आरकेएम) पर कवच लगाने की मंजूरी दे दी है। कवच एक ऐसी व्यवस्था है जो ट्रेन टक्कर को रोकने का काम करती है।
इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के छह महत्वपूर्ण रेल मार्ग खंडों जैसे-बघुआपाल-बुढ़पंक, हरिदासपुर-पारादीप, खुर्दा रोड (केयूआर)-बलांगीर, नौपाड़ा-गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ और बोब्बिली-सलूर को कवर करती है।

स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार

स्वीकृत कार्य भारतीय रेल के उस व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत रेलवे नेटवर्क पर एलटीई-आधारित संचार प्रणाली के साथ कवच प्रणाली को तैनात किया जा रहा है। कवच भारत की स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है, जिसे खतरे के सिग्नल पार करने (एसपीएडी), अति-गति और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोककर सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली ट्रेनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखती है और आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है, जिससे परिचालन सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

बेहतर सुरक्षा, गति और विश्वसनीयता

इन मार्गों पर कवच प्रणाली की स्थापना से स्वचालित ट्रेन सुरक्षा और टक्कर से बचाव की क्षमता बढ़ेगी जिससे ट्रेन संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कवच प्रणाली घने कोहरे सहित प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में भी ट्रेनों की सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय आवाजाही सुनिश्चित करती है, जिससे सेवा की विश्वसनीयता और समयबद्धता में सुधार होता है।

पूर्वी तट रेलवे में सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करना

इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों में यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे उच्च घनत्व वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच नेटवर्क के विस्तार के लिए भारतीय रेल के चल रहे अभियान को और मजबूती मिलेगी।

कच्छ में रेल संपर्क को मिलेगी नई मजबूती, ₹493 करोड़ की दोहरीकरण परियोजना मंजूर

दोहरी लाइन से प्रति वर्ष 12 मीट्रिक टन माल ढुलाई संभव होगी, जिससे रसद मजबूत होगी और औद्योगिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा

सूत्र-रे.स.ब्यू - गुजरात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के आदिपुर-भुज खंड (49 किमी) के दोहरीकरण को 493 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है।
भारतीय रेलवे के मौजूदा दोहरीकरण, तिहरीकरण और अन्य नेटवर्क सुधार कार्यों के माध्यम से क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के तहत यह परियोजना स्वीकृत की गई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस खंड के दोहरीकरण से कच्छ क्षेत्र में रेल संपर्क मजबूत होगा और यात्री एवं माल ढुलाई दोनों में अपेक्षित वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

बढ़ते यातायात गलियारे पर क्षमता वृद्धि

गांधीधाम-नालिया कॉरिडोर पर स्थित आदिपुर-भुज खंड में क्षेत्र में पहले से ही चल रही कई रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के कारण यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में एक सिंगल-लाइन रूट है। इनमें भुज-नालिया गेज रूपांतरण, नालिया-वायोर लाइन का विस्तार और नालिया-जाखौ, वायोर-लखपत और देशालपार-लूना को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइनें शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, भुज-आदिपुर खंड से यात्री और माल ढुलाई में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और भविष्य की यातायात मांग को पूरा करने के लिए दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई है।

यात्री और माल ढुलाई संचालन में सुधार

इस परियोजना से प्रतिदिन दोनों दिशाओं में दो अतिरिक्त यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन में सुविधा होने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
दोहरी लाइन से प्रति वर्ष अतिरिक्त 12 मिलियन टन (एमटीपीए) माल ढुलाई यातायात को भी समर्थन मिलेगा, जिससे पश्चिमी गुजरात में रसद और औद्योगिक संपर्क मजबूत होगा।

भविष्य के विकास और परिचालन दक्षता को समर्थन

इस खंड की वर्तमान क्षमता का उपयोग 2029-30 तक बढ़कर 123 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो समय रहते क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है। दोहरीकरण कार्य से मार्ग पर भीड़ कम होगी, परिचालन संबंधी बाधाएं दूर होंगी और रेल परिचालन की विश्वसनीयता में सुधार होगा। इस परियोजना से यात्रियों और माल ढुलाई में वृद्धि होने से भारतीय रेलवे के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की भी उम्मीद है, साथ ही कच्छ क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस परियोजना की मंजूरी के साथ, भारतीय रेलवे भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण, कनेक्टिविटी में सुधार और बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है।

रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपये की कवच परियोजना को मंजूरी दी

सूत्र-रे.स.ब्यू - रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गुजरात के पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के 48 ब्लॉक खंडों में फैले 598 किलोमीटर मार्ग पर कवच परियोजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना को रेलवे मार्गों पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) आधारित संचार तकनीक के साथ कवच उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत 140 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है।
इससे पहले, अहमदाबाद डिवीजन के लगभग 702 किलोमीटर मार्ग पर कवच के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान परियोजना की मंजूरी के साथ, डिवीजन के शेष खंड भी कवच प्रणाली के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे पूरे डिवीजन में स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है जिसे परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली खतरे के सिग्नल को पार करने (एसपीएडी) से रोकने, गंभीर परिस्थितियों में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर रेल की गति को नियंत्रित करके दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम करती है। रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने और रेल संचालन को आधुनिक बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत पूरे नेटवर्क में कवच कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है।

पनवेल जंक्शन की भीड़ होगी कम, भारतीय रेलवे ने ₹172 करोड़ की कॉर्ड लाइन परियोजना को दी मंजूरी

नई कॉर्ड लाइन से मालगाड़ियों के रुकने के समय में लगभग 110 मिनट की कमी आएगी, जिससे टर्नअराउंड समय और रसद दक्षता को बढ़ावा मिलेगा

सूत्र-रे.स.ब्यू - महाराष्ट्र में रेल क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई की आवाजाही में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य रेलवे के अंतर्गत 172 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 'सोमताने-चिखली कॉर्ड लाइन (3.7 किमी)' के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
यह नई कॉर्ड लाइन कर्जत मार्ग पर चिखली और रोहा मार्ग पर सोमताने के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क की कमी को पूरा करेगी। इससे ट्रेनों को भीड़भाड़ वाले पनवेल जंक्शन में प्रवेश किये बिना या इंजन बदले बिना कर्जत और रोहा कॉरिडोर के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी।

पनवेल जंक्शन पर भीड़भाड़ कम करना

पनवेल मुंबई क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है, जो रोहा, जेएनपीटी, कर्जत और दिवा सहित चार प्रमुख दिशाओं के आने-जाने वाले यातायात को संभालता है। कर्जत और रोहा मार्गों के बीच सीधी कॉर्ड लाइन न होने के कारण वर्तमान में परिचालन संबंधी बाधाएं और भीड़भाड़ होती है, क्योंकि ट्रेनों को पनवेल जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। स्वीकृत कॉर्ड लाइन से सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे ट्रेन संचालन को सुव्यवस्थित करने और नेटवर्क की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

जेएनपीटी से जुडे माल परिवहन को बड़ा बढ़ावा

यह परियोजना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण/ट्रस्ट (जेएनपीए/जेएनपीटी) से जुड़े माल यातायात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो भारत के लगभग 60 प्रतिशत कंटेनर यातायात को संभालता है।
वर्तमान में, कर्जत, जसई और रोहा कॉरिडोर के बीच चलने वाली मालगाड़ियों को पनवेल जंक्शन में प्रवेश करना पड़ता है और आगे बढने से पहले इंजन बदलना पड़ता है। सोमताने-चिखली कॉर्ड लाइन के चालू होने के बाद मालगाड़ियां पनवेल जंक्शन को बाईपास कर सकेंगी, जिससे परिचालन में उल्लेखनीय सुधार होगा।
इस परियोजना से प्रत्येक मालगाड़ी के रूकने के समय में लगभग 110 मिनट की बचत होने की उम्मीद है, जिससे टर्नअराउंड समय और रसद दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अतिरिक्त यातायात क्षमता और नेटवर्क दक्षता

परियोजना के पूरा होने के बाद इस नई कॉर्ड लाइन के माध्यम से प्रति वर्ष नौ मिलियन टन (एमटीपीए) अतिरिक्त माल यातायात का संचालन संभव होगा। यह परियोजना जेएनपीटी-कर्जत और जेएनपीटी-रोहा खंडों पर पहले से स्वीकृत पनवेल एलिवेटेड कॉर्ड लाइनों की पूरक है, जिससे पश्चिमी भारत को सेवा प्रदान करने वाले माल ढुलाई कनेक्टिविटी नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कमी पूरी हो जाएगी।
इस स्वीकृति के साथ भारतीय रेलवे क्षमता विस्तार, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और कुशल माल परिवहन अवसंरचना के विकास पर अपना विशेष ध्यान जारी रखे हुए है, ताकि भारत की बढ़ती रसद और आर्थिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

त्रुटियों की त्वरित पहचान और सुरक्षित संचालन के लिए ₹405 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

> "अधिक भीड़भाड़ वाले और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर 32 स्टेशनों पर रिले-आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से प्रतिस्थापित किया जाएगा"

सूत्र-रे.स.ब्यू- सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेल ने पूर्वी रेलवे पर 405 करोड़ रुपये की सिग्नलिंग उन्नयन परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 32 स्टेशनों पर रिले-आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) सिस्टम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें हाई डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन) और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (एचयूएन) मार्गों पर स्थित 25 पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई)/रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) स्टेशन और 7 इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) स्टेशन शामिल हैं।
यह परियोजना भारतीय रेलवे की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मार्गों पर सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण करना और पूरे नेटवर्क में विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रचालनगत प्रदर्शन में सुधार करना है।

सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय ट्रेन प्रचालनों के लिए आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली

इन मार्गों पर विद्यमान कई सिग्नलिंग प्रणालियां पुरानी रिले प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और पुरानी अवसंरचना के कारण प्रचालनगत संबंधी सीमाओं का सामना करती हैं। साफ और गंदे तारों का पृथक्करण न होना, पुराने बिजली आपूर्ति तंत्र, अनुचित अर्थिंग प्रणाली और पुराने सिग्नलिंग उपकरण जैसी समस्याओं के कारण रखरखाव की आवश्यकता बढ़ गई है और विफलता का जोखिम भी बढ़ गया है।
स्वीकृत परियोजना के तहत इन पुरानी प्रणालियों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तकनीक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो अधिक विश्वसनीयता, बेहतर सुरक्षा और तेजी से त्रुटि का पता लगाने की क्षमता प्रदान करती है।

विफलताओं को कम करने और प्रचालनगत दक्षता में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम (ईआई) उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ट्रेनों की आवाजाही और सिग्नलिंग संचालन को अधिक सटीकता और विश्वसनीयता के साथ नियंत्रित करते हैं। पारंपरिक रिले-आधारित प्रणालियों की तुलना में, ईआई सिग्नलिंग विफलताओं की संभावना को कम करता है, सिस्टम की उपलब्धता में सुधार करता है और त्रुटि की स्थिति में त्वरित बहाली को सरल बनाता है।
आधुनिक सिग्नलिंग अवसंरचना देश के कुछ सबसे व्यस्त रेलवे गलियारों पर सुचारू ट्रेन संचालन में सहायता करेगी, साथ ही यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाएगी।

क्षमता संवर्धन और भविष्य की रेलवे प्रौद्योगिकियों की सहायता करना

यह परियोजना भारतीय रेल के उन निरंतर प्रयासों के अनुरूप है जिनका उद्देश्य उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग और केंद्रीत यातायात नियंत्रण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता करने में सक्षम एक आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का निर्माण करना है।
यह मंजूरी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार और यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए एक सुरक्षित और अधिक कुशल रेलवे नेटवर्क प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय रेलवे ने शहरी आवागमन और रेल-सड़क संपर्क में सुधार के लिए इंदौर यार्ड में शास्त्रीय आरओबी के पुनर्निर्माण को 139 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

सूत्र-रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में शहरी परिवहन अवसंरचना में सुधार और रेल-सड़क संपर्क को बढ़ाने की दिशा में 139 करोड़ रुपये परियोजना को मंजूदी दे दी है। जिसके तहत इंदौर यार्ड में स्थित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) नंबर 103-सी, जिसे लोकप्रिय रूप से शास्त्रीय ब्रिज के नाम से जाना जाता है, का पुनर्निर्माण होना है।

यह परियोजना भारतीय रेलवे के सड़क ओवरब्रिज, सड़क अंडरब्रिज और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के चल रहे कार्यक्रम के तहत मंजूर की गई है, जिसका उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन और सुरक्षा में सुधार करना है।

यातायात की सुगमता के लिए आधुनिक चार लेन का पुल

स्वीकृत परियोजना में 72 मीटर लंबे ऊंट की पीठ के आकार के ढांचे वाले चार लेन के ओवरब्रिज का निर्माण शामिल है, जिसमें पीएससी गर्डर और एक पूर्ण वायडक्ट व्यवस्था होगी। नया पुल बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के साथ-साथ यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय यातायात की सुगमता और रखरखाव के लिए, पुल के नीचे दोनों ओर 6 मीटर चौड़ी सर्विस सड़कें बनाई जाएंगी।

व्यापक अवसंरचना उन्नयन

पुल की संरचना के पुनर्निर्माण के अलावा, इस परियोजना में व्यापक स्तर पर उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करने और आधुनिकीकरण के कार्य शामिल हैं। निर्बाध जल निकासी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सीवर बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित किया जाएगा और नई सीवर लाइनों के निर्माण के माध्यम से इसे उन्नत बनाया जाएगा।

परियोजना में विद्युत अवसंरचना का स्थानांतरण और नवीनीकरण भी शामिल है, जिसमें नए खंभे, प्रकाश व्यवस्था और संबंधित उपकरणों की स्थापना शामिल है, जिससे बेहतर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं और शहरी अवसंरचना का एकीकरण सुनिश्चित होगा।

कनेक्टिविटी और शहरी विकास को बढ़ावा

शास्त्रीय पुल के पुनर्निर्माण से इंदौर में सड़क संपर्क में काफी सुधार होगा, यातायात की भीड़ कम होगी और निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। इस परियोजना से रेलवे और शहरी परिवहन अवसंरचना के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है, साथ ही शहर की बढ़ती आवागमन संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा।

यह मंजूरी आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, यात्रियों और आम जनता की सुविधा में सुधार और देश भर में सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन नेटवर्क के निर्माण के प्रति भारतीय रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारतीय रेल ने प्रमुख कोयला गलियारे की क्षमता बढ़ाने के लिए 755 करोड़ रुपये की चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी

सूत्र-रे.स.ब्यू - बढ़ते कोयला परिवहन, अतिरिक्त माल ढुलाई और नेटवर्क क्षमता में वृद्धि के लिए अत्यधिक इस्तेमाल होने वाले रेल गलियारे का आधुनिकीकरण और उसकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

भारत के कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में रेलवे की क्षमता में सुधार करते हुए, भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) की 42 किलोमीटर लंबी चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है।

इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी-सरगबुंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। इस रेल गलियारे की पहचान भारतीय रेल के 'मिशन 3000 एमटी' और 'उच्च-घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) कॉरिडोर' पहल के तहत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है।

कोरबा, जिसे व्यापक रूप से ''भारत की ऊर्जा राजधानी'' के नाम से जाना जाता है, अनेक ताप विद्युत संयंत्रों का केन्द्र है और देश के सबसे महत्वपूर्ण कोयला परिवहन केन्द्रों में से एक है। चांपा-कोरबा रेल खंड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की कोयला खदानों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क तथा मुम्बई-हावड़ा उच्च घनत्व वाले गलियारे से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल कड़ी के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में इस रेल खंड पर प्रतिदिन लगभग 10 जोड़ी यात्री ट्रेनें और लगभग 55 जोड़ी मालगाड़ियाँ चलती हैं। एसईसीएल और एमसीएल की संयुक्त कोयला उत्पादन क्षमता लगभग 247 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है, जिसके बढ़कर लगभग 450 एमटीपीए तक पहुँचने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में लगभग 200 एमटीपीए अतिरिक्त कोयला यातायात बढ़ने की संभावना है।

तीसरी रेल लाइन परियोजना से परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिचालन में अधिक लचीलापन आएगा तथा मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी।

परियोजना के पूरा होने पर, प्रतिदिन प्रत्येक दिशा में दो अतिरिक्त यात्री ट्रेनें चलने की सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह परियोजना 5.95 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) अतिरिक्त माल ढुलाई में भी सहयोग प्रदान करेगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शुद्ध आय होने का अनुमान है, जिसमें 82 करोड़ रुपये माल ढुलाई से और 3 करोड़ रुपये कोचिंग सेवाओं (यात्री सेवाओं) से प्राप्त होंगे।

तीसरी रेल लाइन से मालगाड़ियों के ठहराव और देरी में भी कमी आएगी। वर्तमान में मालगाड़ियों को प्रत्येक दिशा में लगभग पाँच मिनट की देरी का सामना करना पड़ता है। इस देरी में कमी आने से प्रतिवर्ष लगभग 1.30 करोड़ रुपये की परिचालन बचत होने का अनुमान है।

चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना भारतीय रेलवे के नेटवर्क क्षमता विस्तार, माल परिवहन दक्षता में सुधार, यात्री सेवाओं में सुधार तथा देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा विकास लक्ष्यों को समर्थन देने के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय रेल ने 220 करोड़ रुपए की लागत वाली मारारिकुल्लम-आलप्पुषा दोहरीकरण परियोजना को दी मंजूरी

सूत्र-रे.स.ब्यू - दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम आलप्पुषा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग 220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है।

यह परियोजना रेलवे नेटवर्क की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से स्वीकृत दोहरीकरण, तिहरीकरण, चौथी लाइन, फ्लाईओवर एवं बाईपास कार्यों के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित की गई है। मारारिकुल्लम-आलप्पुषा रेल सेक्शन वर्तमान में एरणाकुलम-तुरवूर-आलप्पुषा-अम्बलप्पुषा-कायमकुलम रेल कॉरिडोर का एकमात्र शेष एकल रेल लाइन सेक्शन है, जबकि इस मार्ग पर अन्य दोहरीकरण कार्य पहले ही चालू किए जा चुके हैं अथवा निर्माणाधीन हैं।

परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिदिन प्रत्येक दिशा में 9 अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही यह परियोजना प्रतिवर्ष 2.88 मिलियन टन माल ढुलाई संभव हो सकेगी। यात्री एवं माल परिवहन में वृद्धि के परिणामस्वरूप लगभग 3.08 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक शुद्ध आय प्राप्त होने का भी अनुमान है।

यह दोहरीकरण कार्य यात्री एवं मालगाड़ियों के ठहराव और प्रतीक्षा समय को कम कर परिचालन दक्षता में सुधार लाएगा, जिससे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर ट्रेनों का संचालन अधिक तेज और सुचारु हो सकेगा। इसके अतिरिक्त रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी, समयपालन में सुधार होगा तथा पूरे क्षेत्र में रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा।

इस परियोजना की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT तथा उच्च घनत्व यातायात नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है। परियोजना आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर (FIRR) 3.99% तथा आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (EIRR) 22.30% आंकी गई है। इसके पूरा होने से रेल परिचालन अधिक कुशल बनेगा, माल ढुलाई और यात्री सेवाओं में सुधार होगा तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। यह परियोजना केरल में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और विकास को नई गति देने की दिशा में भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपये की कवच परियोजना को स्वीकृति दी

'कवच' प्रणाली अंबाला छावनी-लुधियाना, कालका-चंडीगढ़-न्यू मोरिंडा-साहनेवाल तथा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख रेल मार्गों पर स्थापित की जाएगी

सूत्र-रे.स.ब्यू - रेल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंबाला मंडल के शेष ब्रॉड गेज रेल खंडों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना 811 किलोमीटर के मार्ग को कवर करती है और इसके लिए 201 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। इस कार्य को भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर 'एलटीई-आधारित संचार नेटवर्क' के साथ कवच प्रणाली के प्रावधान वाले व्यापक कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है।

इस स्वीकृत कार्य के अंतर्गत अंबाला मंडल के कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग शामिल होंगे, जिनमें अंबाला छावनी-लुधियाना, कालका-चंडीगढ़-न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, सरहिंद-दौलतपुर चौक, राजपुरा-बठिंडा-श्री गंगानगर और लुधियाना-धुरी-जाखल रेलखंड शामिल हैं।

ये मार्ग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ने वाले प्रमुख रेल गलियारों के रूप में कार्य करते हैं। यहां से भारी मात्रा में यात्री और मालगाड़ियों का आवागमन होता है, जो इस पूरे क्षेत्र में लोगों और सामान की आवाजाही में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

'कवच' स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है, जिसे परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली रेड सिग्नल पार करने (एसपीएडी) की घटनाओं को रोकने में मदद करती है, असुरक्षित स्थितियों से बचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है और ट्रेनों की आपस में होने वाली टक्करों के जोखिम को काफी हद तक कम करती है।

भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर अधिक व्यस्तता वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर सुरक्षा, विश्वसनीयता और क्षमता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत चरणबद्ध तरीके से 'कवच' प्रणाली का विस्तार कर रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन, महाप्रबंधक, श्री अमिताभ ने की कार्य की समीक्षा

सूत्र-रे.स.ब्यू - श्री अमिताभ, महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय में दिनांक 25.06.2026 को चारों मण्डलों के मण्डल रेल प्रबन्धकों की उपस्थिति में कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार कार्य समीक्षा बैठक में संरक्षा ,कार्य निष्पादन, निर्माण कार्य, पूंजीगत आय, रेलवे ट्रैक की फेंसिंग, समपार फाटक को बंद करने, यात्री सुविधाएं तथा आय बढ़ाने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में श्री अमिताभ, महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस वित्त वर्ष के प्रथम 2 माह में उत्तर पश्चिम रेलवे का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा है और सामंजस्य और समन्वय के साथ कार्य कर सभी कार्यों को लक्ष्यानुसार करने पर ध्यान देना है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करना है। श्री अमिताभ ने संरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए सतर्कता और सजगता से कार्य करने पर बल दिया

बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मण्डलों के मण्डल रेल प्रबंधको ने मण्डलों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान की तथा प्रगति पर चल रहे कार्यों के बारे में अवगत करवाया। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के कार्यों जैसे नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण, विद्युतीकरण के साथ-साथ स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं से जुडे कार्यों और संरक्षा के प्रमुख मदों रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज, सिगनल कार्यों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की गई।

बैठक में स्टेशन पुनर्विकास के उपरांत उपलब्ध वाणिज्यिक स्थान को लीज पर देने की प्रक्रिया का निर्धारण करने, गैर किराया राजस्व को बढाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सेफ्टी फेंसिंग के प्रगति, समपार फाटक को बंद करने व अप्रोच रोड को सुधारने पर चर्चा की गई। बैठक में यातायात सुविधाओं में विस्तार के लिए नये मेगा टर्मिनल, कोचिंग टर्मिनल, पिट लाइन, प्लेटफॉर्म से सम्बंधित कार्यों के लिए डीपीआर और मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई।

बैठक में महाप्रबंधक महोदय श्री अमिताभ ने सभी अधिकारियों को कार्य निष्पादन को निर्धारित लक्ष्यानुसार पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए ताकि समयानुसार रेल उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके तथा आश्वस्त किया कि मुख्यालय स्तर पर अनुमोदित होने वाले कार्यों के निष्पादन में पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

संपादकीय

योग को अपनाती भारतीय रेलः स्वस्थ कर्मचारी, सुरक्षित यात्रा की दिशा में सार्थक पहल

भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर योग आज केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का वैश्विक संदेश बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय रेल के विभिन्न जोनों, मंडलों, उत्पादन इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर योग सत्रों का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि रेलवे अपने कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है।

भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जहाँ लाखों कर्मचारी दिन-रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, तकनीकी कर्मचारी और अन्य रेलकर्मी अत्यधिक जिम्मेदारी और तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ऐसे में योग केवल स्वास्थ्य सुधार का माध्यम नहीं, बल्कि एकाग्रता, मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रभावी साधन भी है।

रेलवे द्वारा योग को संस्थागत रूप से बढ़ावा देना इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि इससे कर्मचारियों में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, कार्य क्षमता बढ़ाने और जीवनशैली से जुड़ी अनेक बीमारियों के जोखिम को घटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसका सकारात्मक प्रभाव न केवल कर्मचारियों पर पड़ता है, बल्कि यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी दिखाई देता है।

यह पहल केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे के प्रत्येक कार्यालय, कार्यशाला, लोको शेड और स्टेशन पर नियमित योग सत्र आयोजित किए जाएँ। यदि योग को दैनिक कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाए तो यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ संगठन की उत्पादकता और कार्यकुशलता को भी नई दिशा दे सकता है।

भारतीय रेल की यह पहल वास्तव में स्वागत योग्य है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है और जब देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन तंत्र इसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बनता है। स्वस्थ कर्मचारी ही सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय रेल सेवा की सबसे मजबूत नींव हैं। इसलिए योग को भारतीय रेल की कार्य संस्कृति का स्थायी हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता भी है और एक दूरदर्शी कदम भी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 अभूतपूर्व भागीदारी वाले वैश्विक कार्यक्रम के रूप में उभरा है।

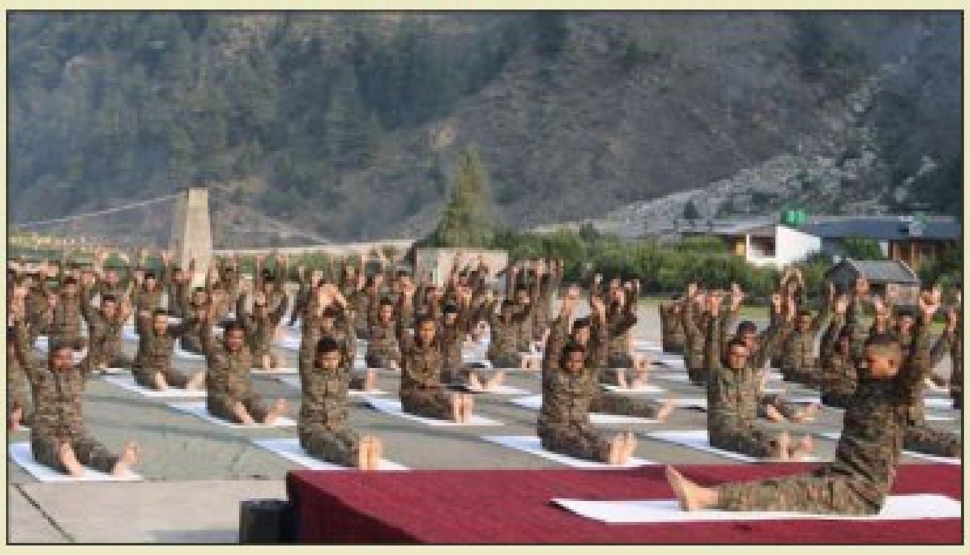

विश्वभर में लाखों लोग 'स्वस्थ आयु के लिए योग' के थीम पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह 2026 में शामिल हुए

योग संगम पोर्टल के अनुसार, 780 जिलों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने समारोह में भाग लिया 7.64 लाख से अधिक संगठन इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में शामिल हुए

सियाचिन से लेकर समुद्रों तक, प्रतिष्ठित विरासत स्थलों से लेकर वैश्विक धरोहरों तक, जगह-जगह हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह 2026 ने योग को स्वास्थ्य और सद्भाव के विश्वव्यापी प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया है

सूत्र-रे.स.ब्यू - 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के अवसर पर भारत और विश्वभर में अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई। इससे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वैश्विक कार्यक्रम के रूप में योग की बढ़ती भूमिका पुनः स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में बड़े पैमाने पर योग प्रदर्शन और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ऐतिहासिक रेड रोड पर हुए कार्यक्रम में 35,000 लोगों ने भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का इस वर्ष का विषय ''स्वस्थ आयु के लिए योग'', शारीरिक फिटनेस, मानसिक लचीलेपन और समग्र कल्याण में योग के योगदान को उजागर करता है जिससे विश्व भर में लाखों लोगों को योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने की प्रेरणा मिली है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 को सही मायने में वैश्विक उत्सव बनाने के लिए संपूर्ण विश्व के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र और कई अन्य देशों सहित विभिन्न महाद्वीपों में योग सत्रों का आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के प्रमुख शहरों तक प्रतिभागियों ने इस उत्सव में भाग लिया। यह स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के लिए योग की विश्वव्यापी स्वीकृति को दर्शाता है।

आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में भारत और विश्व भर के नागरिकों, योग अभ्यास करने वालों, स्वयंसेवकों, संस्थानों और प्रतिभागियों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ''स्वस्थ आयु के लिए योग'' विषय के अंतर्गत कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी ने स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को पुनः स्थापित किया है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ और सुखी भविष्य के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते रहने का आग्रह किया।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने भी 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 समारोह में उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व भर के लोगों की व्यापक भागीदारी जीवन शैली के रूप में योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति को दर्शाती है। उन्होंने इस आयोजन की सफलता में योगदान देने के लिए सभी प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों, आयोजन संस्थानों और हितधारकों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने 'स्वस्थ आयु के लिए योग' विषय का उल्लेख करते हुए समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योग को दैनिक जीवन में निरंतर शामिल करने का आग्रह किया।

भारत में योग के इस उत्सव में राष्ट्रीय नेतृत्व के सर्वोच्च स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित विशाल सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लिया जबकि उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में सांसदों के साथ योग सत्र का नेतृत्व किया जो इसमें राष्ट्रव्यापी भागीदारी की भावना को दर्शाता है।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की ओर से आयोजित ''गंगोत्री से गंगासागर'' अभियान 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का प्रमुख आकर्षण रहा। गंगोत्री से गंगासागर तक लगभग 2,525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस अभियान के अंतर्गत ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और हुगली के प्रतिष्ठित घाटों को क मन योग प्रोटोकॉल सत्रों और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा गया। भारतीय सभ्यता की दो महानतम विरासतों - पवित्र गंगा नदी और योग की प्राचीन प्रथा - को प्रतीकात्मक रूप से एक साथ जोड़ते हुए इस पहल के माध्यम से नदी के किनारे बसे समुदायों के बीच ''स्वस्थ आयु के लिए योग'' और समग्र कल्याण का संदेश दिया गया।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के मुख्य समारोह से पहले जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से योग-थीम वाले कार्यक्रमों की जीवंत श्रृंखला आयोजित की गई। इसके अंतर्गत ''दौड़ से ध्यान'' पहल में कोलकाता के ग्यारह स्थानों पर मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें नागरिकों को योग और स्वास्थ्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समारोह में हुगली नदी के किनारे ''वंदे योगम'' और पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस कार्यक्रम भी शामिल थे जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं तथा जनभागीदारी से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। लगभग 3,000 ड्रोनों के साथ एक भव्य ड्रोन शो ने भारत की योग यात्रा को और भी भव्य तरीके से प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रसिद्ध योग गुरुओं के योगदान को याद किया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले हर ओर उत्साह पैदा हुआ।

दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हर की पौड़ी, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, कर्नाटक में हम्पी स्मारक समूह, लद्दाख में लेह पैलेस, तमिलनाडु में महाबलीपुरम शोर मंदिर, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, असम के सिलचर में कचारी किला, तेलंगाना के हैदराबाद में चारमीनार परिसर, महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, बिहार में नालंदा महाविहार, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी तट और कई अन्य प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित योग सत्रें के माध्यम से देश के हर कोने में इस अवसर पर उत्सवों का आयोजन किया गया।

योग दिवस समारोह में जन भागीदारी की भावना की स्पष्ट झलक आयुष ग्रिड की ओर से विकसित योग संगम पोर्टल पर दिखी जिसने इस कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 780 जिलों में 3.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी दर्ज की। देश भर में आयोजित योग कार्यक्रमों की 7.46 लाख से अधिक तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड की गई, जबकि 2.66 लाख से अधिक भागीदारी प्रमाण पत्र जारी किए गए।

इस पहल के अंतर्गत विश्वभर से 7.64 लाख से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया जिनमें 4.24 लाख सरकारी संस्थान, 2.46 लाख शैक्षणिक संस्थान, निजी संस्थान, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल (3.45 लाख संगठन), राजस्थान (1.67 लाख), मध्य प्रदेश (35,742), असम (25,285) और उत्तर प्रदेश (22,285) इसमें अग्रणी योगदानकर्ताओं में शामिल हैं। इस पर योगा बिलबोर्ड सुविधा को 15,000 से अधिक चित्र भी प्राप्त हुए जिससे देश भर के नागरिकों की व्यापक भागीदारी संभव हो सकी।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 की तैयारियों के दौरान प्राप्त कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों ने इसमें देशव्यापी भागीदारी और वैश्विक पहुंच को उजागर किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में योग दिवस से 75 दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने एक साथ त्रिकोणासन किया जिससे उन्हें आसन करने वाले सबसे बड़े समूह के रूप में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। कान्हा शांति वनम में योग दिवस से 50 दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में 6,000 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ भुजंगासन किया जिससे उन्हें सबसे बड़े समन्वित योग प्रदर्शन के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला। इसके अतिरिक्त, 14 जून 2026 को आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोजित वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,831 दर्शकों के शामिल होने के साथ, यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के सबसे अधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के दौरान सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी के समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, सीआईएसएफ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन पहलों ने नागरिकों के बीच स्वास्थ्य, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ आयु के संदेश को बढ़ावा दिया।

जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और आईडब्ल्यूएआई ने गंगा बेसिन में और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर जहाजों में योग सत्रों का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण की जागरूकता के बीच संबंध को दर्शाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ''वयो योग संगम - स्वस्थ आयु के लिए योग'' का आयोजन किया जिसमें लगभग 1,300 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और बढ़ती आयु में सक्रियता और गरिमामय जीवन के लिए योग के योगदान को उजागर किया।

रक्षा मंत्रालय ने देशभर में व्यापक आयोजन किए जिनमें सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ के रण, पूर्वोत्तर राज्यों और समुद्र में स्थित नौसैनिक अड्डों पर भी योग सत्र आयोजित किए गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व और हजारों सैन्यकर्मियों ने इन आयोजनों में भाग लिया। भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की विभिन्न कमानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए जबकि कई देशों के रक्षा प्रतिनिधियों ने भी इन आयोजनों में भाग लिया जो योग की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया। यह शक्ति, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता के निर्माण में योग के महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने युवाओं के नेतृत्व में सबसे बड़े योग कार्यक्रमों में से एक का आयोजन किया जिसमें 83 लाख से अधिक कैडेट, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, स्थायी प्रशिक्षक और कर्मचारी देश भर में 5,000 से अधिक स्थानों पर समन्वित योग सत्रों में शामिल हुए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का 12वां संस्करण योग के विश्व स्तर पर प्रसार की भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर बन गया है। नागरिकों, संस्थानों, सशस्त्र बलों, युवा संगठनों और वैश्विक समुदायों की भागीदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 ने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ आयु के लिए शाश्वत अभ्यास के रूप में योग की भूमिका को सुदृढ़ किया जिससे विश्व स्तर पर समग्र रूप से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को और मजबूती मिली।

Scanned with OKEN Scanner

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर के करनी स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग सत्र में भाग लिया

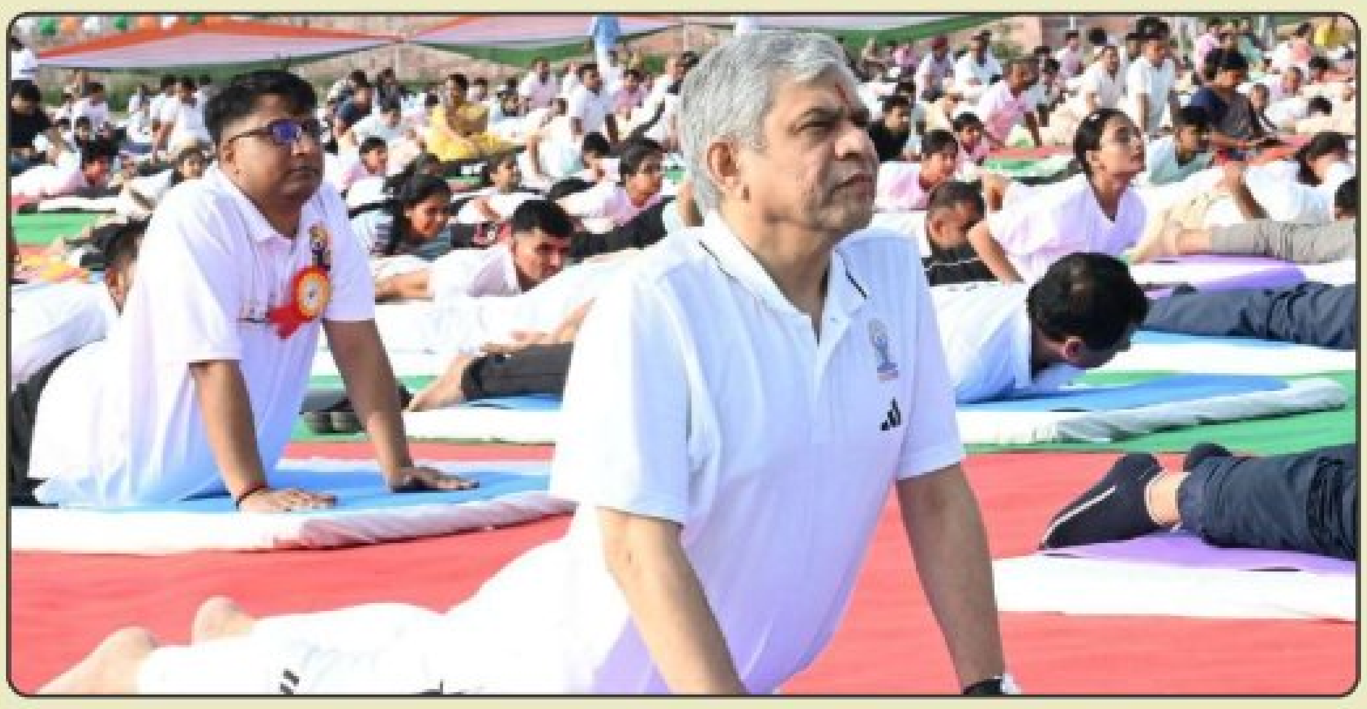

सूत्र-रे.स.ब्यू -केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित एक सामूहिक योग सत्र में भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली तथा योग के महत्व का संदेश दिया।

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में अब पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने कहा कि योग का नियमित अभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और तनावमुक्त जीवन को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण केवल स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के माध्यम से ही हो सकता है। योग अनुशासन, आत्म-संयम और संतुलन सिखाता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

इस अवसर पर करणी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, युवा, महिलाएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया।

चलती वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों के लिए 'माइक्रो योगा' सत्र आयोजित, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन की अनूठी पहल

सूत्र-रे.स.ब्यू- पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली बार चलती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के लिए 'माइक्रो योगा' सत्र आयोजित कर एक अनूठी पहल की। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान योग से जोड़ना और रेल यात्रा के अनुभव को अधिक स्वस्थ, सुखद एवं स्फूर्तिदायक बनाना था।

योग संबंधी निर्देश ट्रेन के ऑडियो सिस्टम के माध्यम से प्रसारित किए गए, जबकि डिब्बों में मौजूद योग स्वयंसेवकों ने यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठे-बैठे योगाभ्यास करने में सहायता की। 10 से 20 मिनट तक चले इस सत्र में यात्रियों ने गर्दन, कंधे, कलाई और बांह के हल्के व्यायाम किए तथा 'ओम' का उच्चारण और ध्यान भी किया।

इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को मोबाइल फोन की स्क्रीन से कुछ समय के लिए दूर रखना, यात्रा के दौरान मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कराना और मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने में मदद करना था। यह पहल चलती ट्रेनों को योग के प्रसार का एक प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करनैल सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ विशेष योग सत्र, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया योगाभ्यास

सूत्र-रे.स.ब्यू - अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करनैल सिंह स्टेडियम में उत्तर रेलवे द्वारा विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देना था।

योग सत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री सतीश कुमार, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार पांडे सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी भी उपस्थित रहे और सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर नियमित जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व पर भी जोर दिया गया तथा कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

गंगा तट पर योग का महाकुंभ, रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एंड एमेनिटीज एसोसिएशन के तत्वावधान में दशाश्वमेध घाट पर भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम

सूत्र-रे.स.ब्यू - 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 की ओर अग्रसर ''गंगोत्री से गंगासागर तक'' विशेष श्रृंखला के अंतर्गत प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट, दारागंज में भव्य योग काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एंड एमेनिटीज एसोसिएशन एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) का अभ्यास कर स्वस्थ शरीर, शांत मन एवं समग्र कल्याण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, आयुष महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) श्रीमती चैत्र वी. द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस दौरान भगवान धन्वंतरि एवं महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र हवन-पूजन संपन्न हुआ। इसके पश्चात घाट के किनारे मनोरम वातावरण में लगभग 850 लोगों ने एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) के अंतर्गत योगाभ्यास कर निरोगी जीवन का संकल्प लिया।

रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एंड एमेनिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज डॉ. नवीन सोनी ने सभी अतिथियों स्वागत किया। श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन योग को भारत की प्राचीन परंपरा तक सीमित न रखकर उसे समग्र स्वास्थ्य, वैश्विक कल्याण और मानवता के बीच सद्भाव का जन-आंदोलन बनाना है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रयागराज में भविष्य में भी नियमित रूप से योग शिविर, जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण का एक प्रभावी माध्यम है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।

इस वृहत्त योग शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुश्री भारती मीणा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री शशिप्रकाश द्विवेदी, अपर महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, श्री गोपाल प्रसाद कुशवाहा, जिला विकास अधिकारी तथा श्री विवेक शुक्ला, उपमेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध भंडार किला (OD Fort), प्रयागराज से श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, राजपत्रित अधिकारी, OD Fort, श्री दीप नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, OD Fort श्रमिक संघ एवं वर्क्स कमेटी सदस्य, श्री अनिल कुमार यादव, उपाध्यक्ष, OD Fort श्रमिक संघ तथा श्री पंकज सिंह, वर्क्स कमेटी सदस्य उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त सिविल डिफेंस से श्री नीरज मिश्रा, एनसीसी कैडेट्स, ब्रह्माकुमारीज, पतंजलि योगपीठ तथा अन्य सामाजिक एवं योग संगठनों के सदस्यों, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ योग क्रियाओं में सहभागिता की। इति इति योगाश्रम के संस्थापक एवं योगाचार्य श्री निशांत कुमार झा द्वारा उपस्थित जनसमूह को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत योगाभ्यास कराया गया।

गंगा तट पर आयोजित यह योग महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एंड एमेनिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं, जिला प्रशासन, आयुष विभाग तथा प्रतिभागियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

> *"कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भारती मीणा, उत्तर मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक शशिप्रकाश द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद कुशवाहा एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपमेला अधिकारी विवेक शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एंड एमेनिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।"*

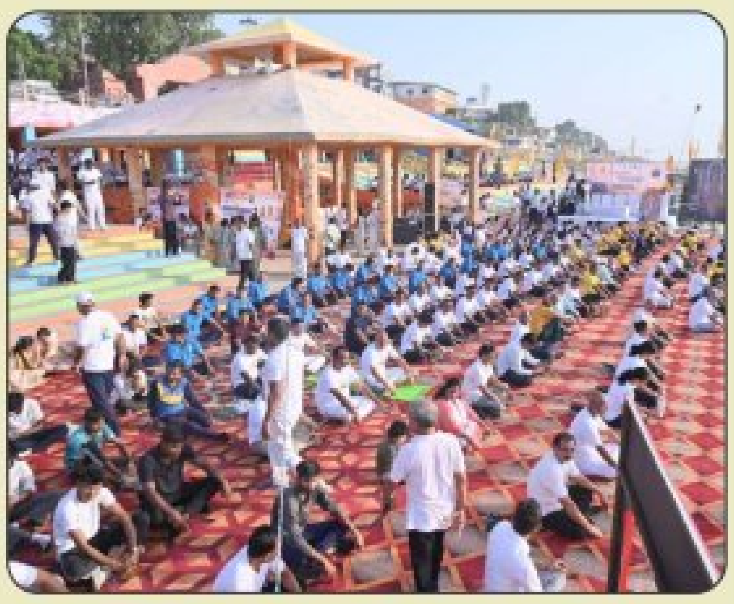

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) और असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन (एआईएसएफ) ने असम में भाषा प्रौद्योगिकी और बहुभाषी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

डिजिटल सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच को सक्षम बनाने और असम के स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साझेदारी

सूत्र-रे.स.ब्यू- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) और असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन (एआईएसएफ) ने असम में भाषा प्रौद्योगिकी, जनरेटिव एआई और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं बहुभाषी डिजिटल सेवाओं, भाषिणी एपीआई के एकीकरण, स्थानीय भाषाओं में अनुवाद सेवाओं, व यस-आधारित समाधानों और भाषाई डेटा संग्रह पर मिलकर काम करेंगी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को भाषिणी की भाषा तकनीक के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बहुभाषी एआई समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सहयोग के तहत सरकारी प्लेटफॉर्म पर एआई-आधारित अनुवाद सेवाओं को मजबूत किया जाएगा, साथ ही भाषा एआई मॉडल और भाषाई डेटासेट में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग एवं क्षमता विकास पर भी काम होगा। डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त कर अधिक समावेशी और सुलभ डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इसके पात्र, स्व-नामांकन और तृतीय-पक्ष अनुशंसाएं दोनों स्वीकार्य

सूत्र-रे.स.ब्यू- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पुरस्कार के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2026 से आरंभ हुए थे और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सभी प्रविष्टियां https://awards.gov.in पर जमा कराई जा सकती हैं।

इस पुरस्कार के लिए 31 जुलाई 2026 तक 5 से 18 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक और अभी भारत में रह रहे बच्चे पात्र हैं। पुरस्कार के लिए स्व-नामांकन और तृतीय-पक्ष अनुशंसाएं दोनों स्वीकार्य हैं। आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण और पुरस्कार की श्रेणी भरनी होगी, और हाल में खिंचा फोटो और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उन्हें अपनी उपलब्धि और उसके प्रभावकारी परिणाम का एक संक्षिप्त विवरण अधिकतम 1000 शब्दों में भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में छह क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इसमें नामांकन की निम्नलिखित श्रेणियां हैं:

वीरता: वे बच्चे जिन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली या असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।

खेलकूद: राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे

सामाजिक सेवा: वे बच्चे जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, वंचितों की सहायता और राष्ट्रीय हितों के कार्यों की पहल की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: बच्चों द्वारा किए गए नवाचार, अनुसंधान या किसी नए उत्पाद, या विचार का प्रारंभिक नमूना या प्रारूप

पर्यावरण: सतत प्रथाएं, जागरूकता अभियान या पर्यावरण संरक्षण नवाचार

कला एवं संस्कृति: संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकला, प्रदर्शन कला या अन्य कलाओं में उत्कृष्ट और असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।

भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है: श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

सूत्र-रे.स.ब्यू- नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग के प्रमुख संगठनों के साथ व्यापार सुगमता पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एफएआईटीएच, एसोचैम, फिक्की, सीआईआई सहित कई उद्योग संगठनों ने भाग लिया और भारत के पर्यटन क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं निवेश-अनुकूल बनाने के उपायों पर चर्चा की।

बैठक में होटल वर्गीकरण प्रणाली को सरल बनाने, निरीक्षण आधारित व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषणा आधारित मूल्यांकन अपनाने, अनुपालन बोझ कम करने, वीजा प्रक्रिया और कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, निवेश और मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा डिजिटल शासन समाधानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पर्यटन परियोजनाओं के लिए बेहतर अवसंरचना, विश्वसनीय पर्यटन डेटा इकोसिस्टम, एंटिटी लॉकर जैसे डिजिटल समाधान और पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

चर्चा के दौरान अनुभवात्मक पर्यटन, होमस्टे, लाइव इवेंट्स और मनोरंजन पार्क जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा पर्यटन सेवाओं में नवाचार और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। पर्यटन मंत्रालय ने उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि वह राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर व्यापार सुगमता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाएगा।

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भांति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजीकृत कार्यालय
502 पंचशीला भवन त्रिवेणी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।

कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिपोर्टर)
कार्यालय 8439 आर्य नगर
पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेणी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

आधार ऐप के डाउनलोड का आंकड़ा 31 मिलियन के पार, यह संख्या लोगों के बीच इसकी बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है

लगभग 40 लाख लोगों ने नए आधार ऐप का उपयोग करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया

लगभग 8.5 लाख लोगों ने आधार ऐप का उपयोग करके अपना पता अपडेट किया

सूत्र-रे.स.ब्यू- आधार ऐप को भारत भर में लोगों के बीच अत्यधिक स्वीकृति मिल रही है। लॉन्च होने के 5 महीने से भी कम समय में इसे 31 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। बढ़ती लोकप्रियता ऐप पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है, क्योंकि यह लोगों को उनकी उंगलियों पर ही सेवाएं उपलब्ध कराता है। जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया नया आधार ऐप लोगों को अपने स्मार्टफोन से ही मोबाइल नंबर अपडेट और पता अपडेट सहित विभिन्न सेवाओं का सुगमता से लाभ उठाने में सक्षम बना रहा है।

अब तक लगभग चार मिलियन लोगों ने नए आधार ऐप का उपयोग करके अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं। वहीं, लगभग 8,50,000 लोगों ने ऐप का उपयोग करके अपना पता अपडेट किया है। आधार ऐप को आधार नंबर धारकों (एएनएच) को अपनी पहचान दिखाने, साझा करने और सत्यापित करने का एक सुविधाजनक और गोपनीयता-प्रथम तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में कई जनहितकारी सुविधाएं हैं, जिनमें एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, उपस्थिति प्रमाण के लिए चेहरे का सत्यापन, प्रमाणीकरण इतिहास और वास्तविक विजिटिंग कार्ड के बजाय संपर्क जानकारी साझा करने के लिए क्यूआर-कोड आधारित संपादन योग्य संपर्क कार्ड शामिल हैं। यह ई-आधार डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है और आधार सेवा केंद्रों (एएसके) आदि पर जाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना सरल बनाता है।

आधार ऐप कई तरह के वास्तविक जीवन के उपयोगों में सहायता करता है। इनमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (ओवीएससई) के क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से होटल चेक-इन शामिल है। यह अस्पताल में भर्ती, आगंतुक प्रबंधन, इवेंट एंट्री, गिग वर्कर्स और सर्विस पार्टनर्स की पहचान सत्यापन जैसे कई अन्य उपयोगों में भी सहायक है।

केंद्र सरकार महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

सूत्र-रे.स.ब्यू- केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई संरचनात्मक और नीतिगत कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख क्षेत्र सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण रहा है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और कार्यबल में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, मिशन शक्ति, योजनाओं के समन्वय और संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। यह देश भर में महिलाओं के लिए कानूनों और सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गवर्नेंस, सुलभता और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। इस ढांचे के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (एसएचई-बॉक्स) पोर्टल विकसित किया गया है, जहां एसएचई-बॉक्स के पिछले संस्करण में एक केंद्रीकृत शिकायत तंत्र उपलब्ध था, वहीं कार्यस्थल इकोसिस्टम के बढ़ते पैमाने और जटिलता ने एक अधिक व्यापक, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल समाधान की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप एसएचई-बॉक्स 2.0 को लॉन्च किया गया।

29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया एसएचई-बॉक्स 2.0 एक सशक्त, प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो संगठित, असंगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उन पर नजर रखने के लिए एक ही स्थान पर सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय स्थापित करता है और एक अधिक संरचित तथा निगरानी योग्य प्रणाली प्रदान करके यौन उत्पीड़न अधिनियम के कार्यान्वयन ढांचे को मजबूत करता है।

गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए पोर्टल में विकेंद्रीकृत निगरानी के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को शामिल करना, केंद्रीय, राज्य, जिला कार्यालयों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आंतरिक समितियों (आईसी) का एक व्यापक भंडार और जिला स्तर पर स्थानीय समितियों (एलसी) को शामिल करना जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं।

एसएचई-बॉक्स 2.0 एक सुरक्षित, गोपनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे महिलाएं बदनामी या प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती हैं। यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में उपलब्ध है, जो विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए समावेशिता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण डिजिटल गवर्नेंस हस्तक्षेप है, जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए माय भारत देशभर में 'वंदे मातरम शिविर' का आयोजन करेगा

सूत्र-रे.स.ब्यू- भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों का विभाग द्वारा 'माई भारत' अभियान के माध्यम से देश भर में वंदे मातरम शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 24 से 30 जून 2026 तक बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और युवा नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख युवा सशक्तीकरण पहल है।

सात-दिवसीय आवासीय शिविरों के रूप में परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी समझ विकसित करने के अवसर प्रदान करना है, साथ ही सांस्कृतिक आत्मविश्वास और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। ये शिविर विकसित भारत/2047 की परिकल्पना के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य सूचित, जिम्मेदार और राष्ट्र-उन्मुख युवा नेताओं की एक पीढ़ी का पोषण करना है।

वंदे मातरम शिविर 'वंदे मातरम' की भावना से प्रेरित हैं जो मात भूमि के प्रति श्रद्धा और क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सीमाओं से परे भावनात्मक एकीकरण का प्रतीक है। यह कार्यक्रम नागरिक भागीदारी, नेतृत्व विकास, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर समकालीन युवाओं की चिंताओं का समाधान करना चाहता है। इस पहल के अंतर्गत चिन्हित जिलों में 20 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 15 से 29 वर्ष की आयु के 150 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रत्येक शिविर में छह राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, पूर्वोत्तर से अनिवार्य प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी होगी। इन शिविरों में लगभग 3,000 युवाओं को शामिल किया जाएगा। इनमें संवैधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लेकर नेतृत्व विकास और प्रमुख योजनाओं तक के विषय शामिल होंगे।

सप्ताह भर चलने वाले इन शिविरों में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका, संविधान और नागरिक कर्तव्यों पर विषयगत सत्र, भाषा, भोजन और खेलों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा, राष्ट्र प्रथम संवाद और तात्कालिक भाषण सत्र, नेतृत्व एवं सामुदायिक एकजुटता कार्यशालाएं और सरकार की प्रमुख पहलों पर चर्चा शामिल होगी। वंदे मातरम शिविर भारत के युवाओं की ऊर्जा, आदर्शवाद और रचनात्मकता का उपयोग करके एकता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र-निर्माण के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

रवनीत सिंह ने जालंधर में दो प्रमुख आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी

सूत्र-रे.स.ब्यू- रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने जालंधर में गुरु नानक पुरा और गढ़ा रोड पर दो प्रमुख रोड ओवर ब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और यात्रियों के लिए सुगम संपर्क सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब रेलवे अवसंरचना और सुरक्षा परियोजनाओं में अभूतपूर्व निवेश देख रहा है। जालंधर सिटी जालंधर कैंट खंड पर लेवल क्र सिंग संख्या B-67A के स्थान पर बनने वाला गुरु नानक पुरा आरओबी यातायात जाम को कम करेगा और रेलवे क्रॉसिंग के बार-बार बंद होने से होने वाली देरी को समाप्त करेगा। व्यस्त सहनेवाल अमृतसर मार्ग पर स्थित यह क्रॉसिंग 4.66 लाख से अधिक ट्रैफिक व्हीकल यूनिट टीवीयू संभालती है। यह परियोजना, जो पहले लागत-साझेदारी आधार पर प्रस्तावित थी, अब लगभग 48.95 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरी तरह रेलवे द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

श्री रवनीत सिंह ने जालंधर सिटी नकोदर खंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या S-4 के स्थान पर गढ़ा रोड पर दो-लेन आरओबी की आधारशिला भी रखी। यह क्रॉसिंग 2.13 लाख से अधिक टीवीयू के साथ भारी वाहन आवागमन का साक्षी है। तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को भी 100 प्रतिशत रेलवे-वित्तपोषित कार्य में परिवर्तित कर दिया गया है।

लगभग 63.98 करोड़ की लागत से बनने वाला गढ़ा रोड आरओबी जालंधर सिटी, जामशेर खास, नकोदर और आसपास के क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा, साथ ही सुरक्षा बढ़ाएगा और यातायात जाम को कम करेगा। सभा को संबोधित करते हुए श्री रवनीत सिंह ने कहा कि ये परियोजनाएँ सुरक्षित सड़कों, तेज आवागमन और बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर हजारों निवासियों को ठोस लाभ पहुँचाएँगी। उन्होंने नागरिकों के हित में अवसंरचना विकास को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्री ने इन परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने में लगे रेलवे अधिकारियों, इंजीनियरों, स्थानीय प्रशासन और अन्य हितधारकों के प्रयासों की भी सराहना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि दोनों आरओबी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

मध्य रेल, मुंबई मंडल द्वारा जेएनपीटी से पहली बार डबल स्टैक कंटेनर रेक का प्रेषण (डिस्पैच)

सूत्र-रे.स.ब्यू- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCC) की जेएनपीटी से कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, दिनांक 20.06.2026 को मुंबई मंडल के माध्यम से पहली बार डबल स्टैक कंटेनर रेक को लोड किया गया। यह रेक जेएनपीटी से संजन गति शक्ति मल्टी-मॉडल टर्मिनल (जो वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन में संजन स्टेशन से जुड़ा है) के लिए रवाना की गई, जिसे मुंबई मंडल के अंतर्गत आने वाले संजन रेलवे स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

45 बीएलसीएम ए/बी वैगनों (बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर मॉडिफाइड फ्लैट वैगन) वाली इस रेक को दिनांक 20.06.2026 को लोड किया गया तथा दिनांक 21.06.2026 को जेएनपीटी से प्रेषित किया गया। इस रेक में कुल 180 टीईयू (TEUs) कंटेनर लोड किए गए, जिनका कुल भार 2,544.07 टन था। यह रेक पश्चिमी डीएफसीसी मार्ग से 232 किलोमीटर की दूरी तय की ।

जेएनपीटी पोर्ट टर्मिनलों से पश्चिमी डीएफसीसी के माध्यम से सीधे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का संचालन माल परिवहन की दक्षता बढ़ाने, पारगमन समय कम करने तथा बंदरगाह से माल निकासी क्षमता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत बनाने, सड़कों पर यातायात दबाव कम करने तथा राष्ट्रीय रेल योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जेएनपीटी से पश्चिमी डीएफसीसी के माध्यम से डबल स्टैक कंटेनर परिचालन की शुरुआत के साथ ही दिनांक 20.06.2026 को दो अन्य डबल स्टैक कंटेनर रेक भी लोड की गई उनका विवरण निम्नानुसार है।

1. जेएनपीटी से GDGH (गढ़ी हरसरू, दिल्ली मंडल)
2. जेएनपीटी से CGMV (छोटा उदयपुर, वडोदरा मंडल)

रेलवे बोर्ड ने वैगन डिजाइन नीति में बड़े सुधारों को लागू करने का निर्णय लिया रेल मंत्री ने अगले 15 दिनों के भीतर नई वैगन डिजाइन नीति जारी करने के निर्देश दिए

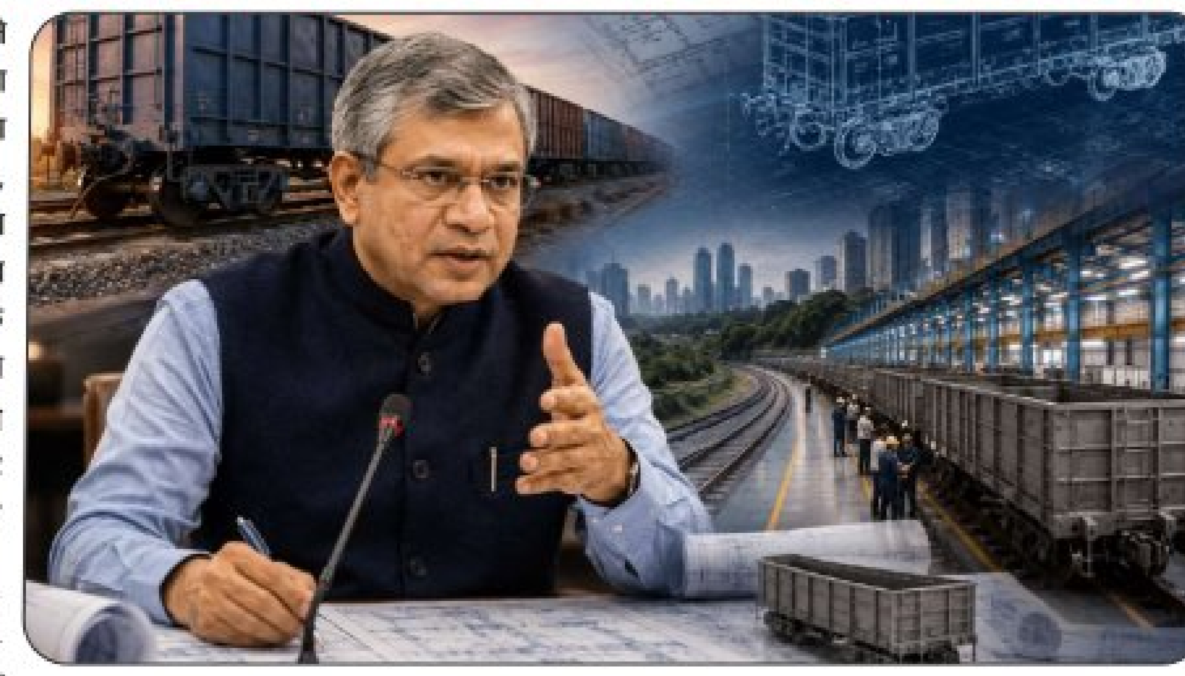

सूत्र-रे.स.ब्यू- माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि देश में माल परिवहन का अधिकाधिक हिस्सा रेल के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परिवहन का एक अधिक हरित एवं ऊर्जा-कुशल साधन है। भारतीय रेल के लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के निकट पहुँचने के साथ, रेल-आधारित माल परिवहन में वृद्धि से देश की आयातित डीजल पर निर्भरता कम हुई है तथा पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिला है।

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें भारतीय रेल को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए माल परिवहन का पसंदीदा माध्यम बनाने हेतु सुधारों पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना एवं श्री रवनीत सिंह बिट्टू, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के महानिदेशक, रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस दिशा में भारतीय रेल विभिन्न उद्योगों, व्यापारिक संगठनों तथा प्रमुख माल ग्राहकों के साथ विस्तृत परामर्श कर रही है, जो अनेक ऐसी वस्तुओं से जुड़े हैं जिनमें रेल परिवहन की व्यापक संभावनाएं हैं। इन चर्चाओं के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि यदि वैगनों के डिजाइन को विभिन्न वस्तुओं की विशिष्ट हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, तो रेल परिवहन को अधिक व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है।

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि सीमेंट एवं नमक जैसी वस्तुओं के लिए हाल ही में विकसित विशेषीकृत वैगनों की सफलता ने यह सिद्ध किया है कि उद्योगों की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप वैगनों का डिजाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तु-विशिष्ट वैगनों ने लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया है, जिससे रेल लॉजिस्टिक्स की आकर्षण क्षमता बढ़ी है।

इसी क्रम में भारतीय रेल ने वर्तमान वैगन डिजाइन नीति में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है। विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषीकृत वैगनों के विकास हेतु एक उद्योग-अनुकूल ढांचा प्रदान करने के लिए नई वैगन डिजाइन नीति अगले 15 दिनों के भीतर तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

रेलवे बोर्ड ने वैगन डिजाइन नीति में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित नीति के अंतर्गत उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वैगनों का डिजाइन तैयार कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, स्टील कॉइल्स के परिवहन हेतु विशेष बाइंडिंग व्यवस्था एवं समर्पित लोडिंग-अनलोडिंग प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य अनेक वस्तुओं की भी अपनी विशिष्ट परिचालन आवश्यकताएँ हैं। नई व्यवस्था के तहत उद्योगों को अपनी जरूरतों के अनुसार वैगनों के डिजाइन में परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वैगनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आरडीएसओ एवं सीसीआरएस की रहेगी। इन सुधारों से भारतीय रेल के साथ अनेक नए उद्योगों के जुड़ने की संभावना बनेगी।

यह सुधार रेलवे माल परिवहन तंत्र में तथा वैगन विकास में नवाचार को बढ़ावा देगा। वस्तु-विशिष्ट परिवहन समाधान उपलब्ध कराकर भारतीय रेल नए माल परिवहन स्रोतों को आकर्षित करने, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रेल की हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

उद्योगों को सड़क से रेल की ओर अधिक मात्रा में माल परिवहन स्थानांतरित करने में सक्षम बनाकर नई वैगन डिजाइन नीति हरित रेलवे एवं हरित लॉजिस्टिक्स के विजन को आगे बढ़ाएगी। रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक पर्यावरण-अनुकूल है तथा भारतीय रेल के लगभग पूर्ण विद्युतीकरण के साथ रेल आधारित माल परिवहन में वृद्धि से आयातित डीजल पर निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा आवश्यक वस्तुएं आम नागरिकों के लिए अधिक किफायती बन सकेंगी।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे में जैबिल के नये उन्नत विनिर्माण संयंत्र और उच्च रोजगार क्षमता वाले निर्यात केंद्रित डेटा सेंटर इकोसिस्टम का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना के तहत एआई डेटा सेंटर एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभर रहे हैं: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

सूत्र-रे.स.ब्यू- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बुधवार, 17 जून, 2026 को पुणे के रंजंगांव में जैबिल इंक की उच्च तकनीक वाले उन्नत विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें वरिष्ठ नेता श्री दिलीप वलसे पाटिल, युवा नेता श्री ज्ञानेश्वर कटके, श्री एंडी प्रीस्टली (जैबिल सर्किट्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीओओ), महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जावान अधिकारियों के साथ-साथ पूरी जैबिल टीम शामिल थी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक प्रगति का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है। उन्होंने देश के भीतर इसके बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की रणनीतिक आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज विश्व भर में एआई डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा विकास इंजन बन गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत यह सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि इन डेटा सेंटरों को शक्ति प्रदान करने वाले प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण देश में ही हो। जैबिल पुणे में अपनी आधुनिक, उन्नत और उच्च तकनीक वाले संयंत्र के माध्यम से इन महत्वपूर्ण डेटा सेंटर के घटकों का निर्माण करेगी। असाधारण परिचालन क्षमता से युक्त यह संयंत्र भारत की घरेलू तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ विश्व भर के बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना की। इन लक्षित पहलों के बदौलत, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी के रूप में तेजी से प्रगति की है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, तैयार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाहित करने वाला यह नया एकीकृत तंत्र महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभों को उजागर करने के लिए तैयार है।

Scanned with OKEN Scanner

New SOS Feature Aims to Make Mumbai's Local Trains Safer for Women

Central Railway and Yatri App introduce a technology-driven emergency response system with automatic location and journey tracking.

Source/RSB- Central Railway's Railway Protection Force in collaboration with the Yatri App launched the SOS Safety feature in Yatri App, on 23.06.2026, to enhance the security of Women commuters on Mumbai's suburban network.

The feature was officially inaugurated at a launch event on 23.06.2026, at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station The Divisional Security Commissioner (DSC), Mumbai Division Central Railway, Senior Officers of Central Railway, Founder and Co-Founders of - Yatri App staff of Central Railway and Yatri App were also present during the event.

Mumbai's local railway network is one of the largest and busiest in the world, serving lakhs of women commuters every day. The SOS feature provides these commuters with a direct, technology powered link to the RPF in moments of distress while travelling on local trains, platforms, foot-over bridges (FOBs), or station areas. Upon activation, the feature automatically shares the commuter's live location and key journey details including train number, route, rake information, and nearest stations to enable faster identification and a more effective response.

The SOS feature of the Yatri App provides faster access to help with reduced effort in communicating location during emergencies, and an added layer of safety during late-night and early-morning journeys.

It also enables the RPF get real-time access to the commuter's precise train-specific data and location, leading to improved field coordination and significantly reduced emergency response times.

This initiative marks a significant step towards technology-driven policing and passenger safety on Mumbai's suburban system. Central Railway reiterates its commitment to ensuring safe travel for women and remains dedicated to ensuring a safe, secure and comfortable travel experience for all passengers

How the SOS Feature Works

- Targeted Visibility: The SOS icon is visible only to users who have selected female as their gender profile in the Yatri app.
- Night time Security: The feature is actively monitored and operational daily from 10:00 PM to 6:00 AM.
- Accidental Protection: A 5 second cancellation window helps prevent accidental alerts.
- Automated Data Sharing: Unlike traditional emergency helplines, no manual location sharing is required. once triggered, the alert instantly securely transmits live location, train number, route, rake information, and nearest stations straight to the RPF Control Room.

Northern Railway Installs 500 Free Sanitary Napkin Vending Machines at 175 Stations

Source/RSB- In a significant initiative to improve women's hygiene and menstrual health facilities, telecom infrastructure company Indus Towers, in partnership with Northern Railway, has installed 500 sanitary napkin vending machines under its CSR programme, Nari Samman. The machines have been deployed across 175 railway stations in the Delhi, Firozpur, Ambala, Moradabad and Lucknow divisions. Equipped with IoT enabled monitoring systems, they provide free sanitary napkins to women passengers round the clock, helping address an essential hygiene need during travel.

The initiative aims to make railway stations more women friendly while promoting menstrual hygiene awareness and improving access to basic healthcare amenities in public spaces. According to the release, the vending machines have dispensed approximately 3 crore sanitary napkins to date, highlighting the scale and impact of the programme. The facility is expected to benefit thousands of women travellers by ensuring convenient access to sanitary products during journeys, particularly in emergency situations and on long distance routes. The initiative is also expected to enhance passenger convenience and support women's health and well-being across the railway network.

Embark on a Divine Journey with IRCTC's "Kashi Tirtha Yatra

Source/RSB- "The Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)/Southern Zone, has announced an exclusive Bharat Gaurav Tourist Train tour titled "Kashi Tirtha Yatra", covering the sacred destinations of Gaya, Kashi (Varanasi), Prayagraj and Ayodhya in an 08 Nights / 09 Days pilgrimage package.This comprehensive 9 day religious and cultural tour spans from September 9 to September 17, 2026, taking travelers on a sacred round trip journey from Tirunelveli to India's iconic spiritual hubs, including Gaya, Varanasi, Ayodhya, and Prayagraj With the composition of 1- AC Two Tier Coach, 7-AC Three Tier Coaches, 3- Sleeper Class Coaches, 1- Pantry car & 2- Luggage cum Brake Vans, Bharat Gaurav Train (SZBG43) "Kashi Tirth Yatra" will commence service from Tiruenelveli on 09th September, 2026 (Wednesday) via Virudunagar, Madurai, Dindigul, Trichy, Vriddhachalam, Villupuram, Chengalpattu and Chennai. The return journey will commence on 15th September, 2026 to reach Tirunelveli on 17th September, 2026The train will have stoppages at Virudunagar, Madurai, Dindigul, Trichy, Vriddhachalam, Villupuram, Chengalpattu and Chennai for boarding and deboarding with destination stoppages at Gaya, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj

Baby Python rescued from Train

Source/RSB- An Indian Rock baby Python was rescued from the Loco of Train no 12052 Madgaon CSMT Janshatabdi Express on platform no 11 at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus on 24.06.2026.

On 24.06.2026 Shri N K Parsoya, Loco Pilot of Loco no. 22936/SRC/CAB2/WAP4 of Train no. 12052 Madgaon CSMT Janshatabdi Express, after arrival of train at CSMT PF no. 11 at 00:45 hrs noticed a baby python in CAB no.2 (working Mumbai end cab) and informed his reliever Loco Pilot, Shri Omprakash Ram.

All concerned officials were also informed and soon Shri Abhishek Ashok Thavre, Honorary Animal Welfare Officer, Maharashtra State, rushed to the scene. Taking appropriate precautions, the baby python was safely rescued around 1:40 hrs ensuring that railway operations continued without disruption. It was later set free in its natural habitat.

The Indian Rock Python, found in India, is a non-venomous snake and a protected species under the Indian Wildlife Protection Act. It plays a crucial role in maintaining the ecological balance of the food chain.

The current period marks the time when python eggs hatch and the young emerge. With the onset of the monsoon in Mumbai and across Maharashtra, wildlife often seeks shelter in human settlements or other seemingly safe locations. It is speculated that this python hatchling entered the railway engine seeking shelter or protection from the rain and was transported to the location in this manner.

Such incidents can occur during the monsoon or at any other time. In such situations, citizens should not panic or attempt to catch or kill the snake; instead, they should immediately contact the Forest Department or trained snake rescuers. It is essential to carry out rescues in a manner that ensures both wildlife conservation and human safety.

Central Railway commends the swift alertness of its locomotive crew and the timely assistance of the Animal Welfare Officer, which ensured a successful rescue with zero impact on train operations. This incident highlights Central Railway's ongoing commitment to safety, quick crisis response, and the preservation of wildlife. Passengers and citizens are reminded to remain vigilant during the monsoon season and to promptly report any wildlife sightings to railway authorities or forest officials to ensure proper and safe handling.

Modern Food Plaza Launched at Visakhapatnam Railway Station to Enhance Passenger Experience

Source/RSB- A modern Food Plaza for rail users was inaugurated on Platform No. 1 of Visakhapatnam Railway Station on Thursday. The facility, awarded by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to Sri Sai Enterprises, is designed to provide a state-of-the-art dining experience for passengers.

The plaza has seating for more than 100 people and includes both air-conditioned and non air conditioned dining areas. According to officials, it is equipped with modern amenities and aims to offer hygienic, quality food options to meet the diverse preferences of rail users.

Scanned with OKEN Scanner

New Railway Rules in Effect: Indian Railways Revises Fines for Multiple Passenger Offences

Source/RSB- Indian Railways has implemented revised penalties for a wide range of passenger and railway related offences with effect from 20 June 2026, introducing stricter fines for violations ranging from ticketless travel and unauthorized entry into reserved coaches to trespassing, illegal hawking, smoking, and carrying prohibited goods. The revised penalty structure is intended to promote greater passenger discipline, discourage violations of railway rules, ensure smoother train operations, safeguard railway property, and enhance the safety, security, and comfort of passengers across the railway network. The move also seeks to reduce incidents that disrupt railway services and improve compliance with existing regulations. Railway authorities have appealed to passengers to familiarize themselves with the revised penalties, strictly follow railway rules during their journey, and extend full cooperation to Ticket Travelling Examiners (TTEs) and Railway Protection Force (RPF) personnel during ticket inspections, security checks, and other enforcement drives conducted across stations and trains.

Penalties introduced from 20 June 2026 include:

1) **Travelling without ticket- 500/-**
2) **Travelling on another's ticket- 500/-**
3) **Illegal hawking- 2000/-**
4) **Drunkenness & nuisance- 1000/-**
5) **Abusive language- 1000/-**
6) **Obstruction to railway staff duty- 2500/-**
7) **Tresspassing- 500/-**
8) **Refusal to deboard reserved coach without valid ticket- 2000/-**
9) **Disobedience to drivers & conductors- 500/-**
10) **Travelling in ladies coach by male passengers- 2500/-**
11) **False goods declaration- 500/- per quintal**
12) **Carrying offensive goods- 10000/-**
13) **Defacing public notices- 2000/-**
14) **Smoking- 2000/-**

IRCTC Chairman & MD Sanjay Kumar Jain Resigns, Railways to Appoint Interim Chief

Source/RSB- Sanjay Kumar Jain, Chairman and Managing Director of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, has resigned from his position citing personal reasons and will step down with effect from July 20. According to a regulatory filing, IRCTC received a communication from the Ministry of Railways on June 23 conveying approval of the competent authority for Jain's resignation through a letter dated June 22. The Ministry also informed the company that orders regarding the assignment of additional charge of the CMD post will be issued separately. In his resignation, Jain cited personal reasons and acknowledged the contributions of employees and stakeholders to the company's growth. He also highlighted IRCTC's transformation from a Mini Ratna to a Navratna public sector enterprise and its elevation from a Schedule 'B' to a Schedule 'A' Central Public Sector Enterprise during his tenure.

RVNL CMD Saleem Ahmad Gets Additional Charge of IRCON

Source/RSB- Saleem Ahmad, Chairman and Managing Director (CMD) of Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), has been entrusted with the additional charge of CMD of IRCON International Ltd for a period of one year, according to a Ministry of Railways order.

The appointment follows the retirement of incumbent IRCON CMD Hari Mohan Gupta, who superannuates on June 30. An order issued by the Ministry of Railways on June 23 confirmed the arrangement. As per the order, Ahmad will hold additional charge of IRCON for one year from the date he assumes office, or until a regular CMD is appointed, or until further orders whichever is earlier.

With the appointment, Ahmad becomes the head of two major railway public sector undertakings simultaneously. Officials said the move is intended to ensure continuity in IRCON's operations while the government identifies a permanent appointee.

Advancing Railway Safety: RDSO and ARAI Conduct Full-Scale Crashworthiness Test of LHB Coaches

Source/RSB- The Research Designs and Standards Organisation (RDSO), in collaboration with ARAI, Pune, successfully conducted a full-scale crashworthiness test of LHB coaches at its dedicated crash test facility on 24 June 2026. The test involved one LSL-RD coach and one LWSPP coach.

Conducted in accordance with the international standard EN 15227, the test aimed to validate the crashworthy design features of the coaches and generate critical data on coach behaviour during collisions.

The findings will help strengthen future railway coach designs, improve passenger safety, and support the development of safer rolling stock for Indian Railways. Such tests play an important role in validating crashworthy design features and generating engineering data to support the development of safer railway coaches.

GM South Coast Railway Reviews Zone-Wide Safety Preparedness, Focuses on Passenger Security

Source/RSB- General Manager of South Coast Railway, Shri Sandeep Mathur, conducted a comprehensive review of safety preparedness across the railway zone with Principal Heads of Departments and Divisional Railway Managers from all four divisions. The meeting focused on improving punctuality, strengthening safety and security measures, and ensuring resilient and seamless train operations across the network.

During the review, special emphasis was placed on the safety and security of passengers both onboard trains and at railway stations. Reaffirming South Coast Railway's commitment to operational excellence, Shri Sandeep Mathur highlighted the importance of maintaining the highest standards of safety, security, and passenger service to ensure a safe and reliable travel experience for passengers.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner